RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 117
दि. 27.08.2025, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गणेश चतुर्थी पर्व पर नागरिकों को शुभकामनाएँ दीं

गांधीनगर, 26 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सभी नागरिक भाई-बहनों को गणेश चतुर्थी पर्व की शुभकामनाएँ दी हैं।

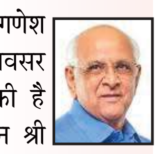

श्री पटेल ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कामना व्यक्त की है कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेशजी की उपासना का यह पर्व हर प्रकार के विघ्न-संकट का निवारण कर राष्ट्र व राज्य की प्रगति, सुख-समृद्धि तथा विकास को और बल प्रदान करेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से इकोफ्रेंड्ली गणेश स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण के साथ श्रीजी की आराधना-उपासना करने का भी अनुरोध किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हांसलपुर प्लांट से प्रथम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल 'ई-विटारा' को दिखाई हरी झंडी

गांधीनगर, 26 अगस्त : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद जिले के हांसलपुर में मारुति-सुजुकी के प्रथम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (बीईवी) और लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के शुभारंभ अवसर पर भारत और जापान की मित्रता को 'मेड फॉर इच अदर' बताते हुए कहा कि अब से दुनिया के 100 से अधिक देशों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, उन पर 'मेड इन इंडिया' लिखा होगा, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है।

प्रधानमंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल' को प्रोत्साहन देते हुए 'स्वदेशी' की अपनी व्याख्या को स्पष्ट करते हुए कहा कि निवेश चाहे किसी भी देश का हो, लेकिन उसमें पसीना किसी किसी भारतीय नागरिक का हो और वह वस्तु भारत की भूमि पर बनकर तैयार हुई है, तो हमारे लिए वह स्वदेशी ही है।

प्रधानमंत्री ने सुजुकी मोटर प्लांट में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते और ग्रीन मोबिलिटी के लिए वैश्विक हब के रूप में भारत के उद्भव को रेखांकित करते हुए, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन 'ई-विटारा' को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने टीडीएसजी लिथयम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन प्लांट का भी उद्घाटन किया।

यह प्लांट स्वच्छ ऊर्जा को गति देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कुल उत्पादन का 80 फीसदी हिस्सा भारत में ही हो।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के हमारे लक्ष्य की दिशा में यह एक बड़ी छलांग है। उन्होंने कहा कि आज से भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का 100 से अधिक देशों में निर्यात होगा और आज से शुरू होने जा रहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन भी भारत और जापान की मित्रता को एक नया आयाम देगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर भावपूर्ण विदाई दी गई

गांधीनगर, 26 अगस्त :प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात की दो दिवसीय यात्रा पूर्ण कर मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भावपूर्ण विदाई दी।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सी. आर. पाटिल, राज्य के प्रोटोकॉल मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, राज्य के मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुनयना तोमर, एयर मार्शल एस. श्रीनिवास, अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त श्री जी.

एस. मलिक, मेजर जनरल गौरव बग्गा तथा मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी श्री ज्वलंत त्रिवेदी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री को भावपूर्ण विदाई दी।

भारत- दक्षिण अफ्रीका संयुक्त कृषि कार्य समूह की वर्चुअल बैठक

दोनों पक्षों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग को और अधिक बढ़ाने के अवसरों को तलाशा

बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया

(जीएनएस)।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पाँचवीं बैठक आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई। बैठक की सह- अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव (स्वतंत्र प्रभार) श्री अजीत कुमार साहू और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग के कार्यवाहक निदेशक श्री तपसना मोलेपो ने की। दोनों पक्षों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ाने की दिशा में इस बैठक को एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में रेखांकित किया।

श्री अजीत कुमार साहू ने कृषि

और संबद्ध क्षेत्रों का अवलोकन प्रस्तुत किया और भारत की उल्लेखनीय कृषि उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई, कई नवीन पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें डिजिटल समाधानों का उपयोग, जलवायु- अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जोखिम न्यूनीकरण और सरकार की ऋण पहल शामिल हैं।

श्री थापसना मोलेपो ने कृषि क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख प्राथमिकताओं का अवलोकन प्रस्तुत किया और भारत के साथ अपनी मूल्यवान साझेदारी को बढ़ाने के लिए अपने देश की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने विस्तार सेवाओं, क्षमता निर्माण और बीज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में दक्षिण अफ्रीका की गहरी रुचि को रेखांकित किया।

चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने दक्षिण अफ्रीका की कृषि अनुसंधान परिषद (एआरसी) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बीच सहयोग को और गहरा करने के अवसरों पर विचार- विमर्श किया। बैठक में मुख्य रूप से ज्ञान का आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान पहल, क्षमता निर्माण और बाजार पहुँच के मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

केंद्र ने 31 मार्च, 2026 तक के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा संशोधित की

समग्र खाद्य सुरक्षा को प्रबंधित करने और जमाखोरी व बेईमानी से की जाने वाली सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकताओं पर गेहूं संबंधी स्टॉक सीमा लागू की। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर आवाजाही प्रतिबंधों को हटाना (संशोधन) आदेश, 2025 27 मई, 2025 को जारी किया गया और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू था। आगामी त्यौहारी सीजन से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक के लिए लागू गेहूं स्टॉक सीमा में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

लोक सभा अध्यक्ष भुवनेश्वर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

ओडिशा के राज्यपाल; मुख्य मंत्री; केंद्रीय मंत्री; राज्य सभा के उप सभापति ; ओडिशा विधान सभा के अध्यक्ष, ओडिशा के उप-मुख्यमंत्री; संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापति इस सम्मेलन में भाग लेंगे

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों के 120 से अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे

सम्मेलन का विषय है - "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका"

(जीएनएस)।

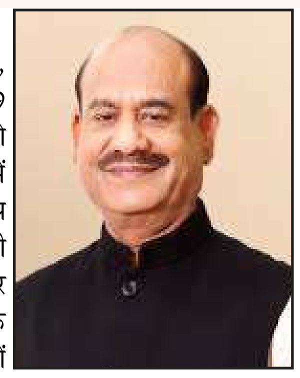

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 29 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर, ओडिशा में संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री बिरला इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे । इसके साथ ही एक स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा।

ओडिशा के मुख्य मंत्री, श्री मोहन चरण माझी; केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम; केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभापति, डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट जनसभा को संबोधित करेंगे। संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापति और सदस्य; ओडिशा सरकार के मंत्री और ओडिशा विधान सभा के सदस्य उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाएँगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान ओडिशा विधान सभा की अध्यक्ष, श्रीमती सुरमा पाढ़ी स्वागत भाषण देंगी और ओडिशा विधान सभा के उपाध्यक्ष, श्री भवानी शंकर भोई धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन (29-30 अगस्त 2025) में संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों और सदस्यों सहित 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका"।

30 अगस्त, 2025 को ओडिशा के राज्यपाल, डॉ. हरि बाबू कंभमपति के विदाई भाषण के साथ सम्मेलन का समापन होगा।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला, राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभापति, डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते, ओडिशा विधान सभा की अध्यक्ष, श्रीमती सुरमा पाढ़ी, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री, श्री के. वी. सिंह देव और श्रीमती प्रवती परिदा भी समापन सत्र में सभा को संबोधित करेंगे । ओडिशा विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति, श्री भास्कर मधेई धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

इस सम्मेलन में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए संवैधानिक सुरक्षोपायों को सुदृढ़ करने, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों 284 करोड़ रुपये से अधिक जारी

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तीन राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के संयुक्त अनुदान जारी किए हैं। मिजोरम को वर्ष 2023-24 के अनुदान के

हिस्से के रूप में 827 पात्र ग्राम परिषदों के लिए 14.2761 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि ओडिशा को 6,085 पात्र ग्राम पंचायतों और 63 पात्र ब्लॉक पंचायतों के लिए 240.8149 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और त्रिपुरा को वित्तीय वर्ष 2025-26 के संयुक्त अनुदान की पहली किस्त के हिस्से के रूप में 606 पात्र ग्राम पंचायतों, 35 पात्र ब्लॉक पंचायतों, 8 पात्र जिला परिषदों के साथ-साथ राज्य की सभी 587 ग्राम समितियों आदि के लिये।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आरटीआई जर्नल का विमोचन किया और एनएफआईसीआई वेबसाइट पर ई-जर्नल का शुभारंभ किया

सीआईसी और राज्य आयोगों ने कोविड लॉकडाउन के दौरान भी लगभग 100 प्रतिशत आरटीआई मामलों का निपटान किया: डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज आरटीआई जर्नल का नवीनतम संस्करण जारी किया और भारतीय राष्ट्रीय सूचना आयोग संघ (एनएफआईसीआई) की वेबसाइट पर एक ई-जर्नल का अनावरण किया।

डॉ. सिंह नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में भारतीय राष्ट्रीय सूचना आयोग संघ की 15वीं वार्षिक आम सभा की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया,

राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों और देश भर के सूचना आयुक्तों ने भाग लिया।

2014 के बाद से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में हुए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में बात करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने 1600 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म करने का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित कराने की प्रथा समाप्त किए जाने से यह संदेश गया है कि यह सरकार देश के युवाओं पर भरोसा करती है, जो देश की 70 प्रतिशत आबादी है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने नागरिक-केंद्रित शासन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना के सार्वजनिक प्रकटीकरण को बढ़ावा देने के लिए पिछले एक दशक में सरकार द्वारा दिए गए व्यापक प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के सिद्धांत के तहत, किस तरह से प्रौद्योगिकी-संचालित विकल्पों के माध्यम से विश्वसनीयता, निपटान दर और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव किए गए।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री ने कोच्चि में एनएमडीएफसी एससीए की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के दक्षिणी क्षेत्र की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 26 अगस्त, 2025 को केरल के कोच्चि में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने की।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) स्व-रोजगार और आय-सृजन उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करके अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करता है, जिसमें महिलाओं और व्यावसायिक समूहों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र प्रदेश प्रशासनों द्वारा नामित एससीए के साथ-साथ पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक के माध्यम से किया जाता है।

बैठक में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अन्य भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों के एससीए के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्हें संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने सहकारी संघवाद के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि राज्य 95 प्रतिशत सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं।

श्री कुरियन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भागीदारी और सूचना का अधिकार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तत्व हैं और कहा कि हर नागरिक, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी शामिल हैं, को उन सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जो उनके कल्याण के लिए बनाई गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का जैन-जैनेतर नागरिकों को 'मिच्छामि दुक्कड़म्'

गांधीनगर, 26 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जैन एवं जैनेतर नागरिक भाई-बहनों को संवत्सरी पर्व के अवसर पर 'मिच्छामि दुक्कड़म्' प्रेषित किया है।

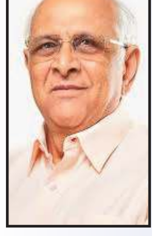

श्री पटेल ने पर्युषण महापर्व को क्षमापना एवं उपकार स्मरण का पर्व बताते हुए कहा है कि मन, वचन तथा कर्म से जाने-अनजाने हुई भूलों की क्षमा-याचना का यह पर्व है।

उन्होंने श्रद्धा भी व्यक्त की है कि भगवान श्री महावीर के क्षमा, संतोष, सरलता, विनम्रता, करुणा एवं जीवदया के सिद्धांतों को सामाजिक जीवन में आत्मसात करने वाला यह पर्युषण पर्व सामाजिक समरसता व मानवता की शक्तियों को अधिक प्रगाढ़ बनाएगा।

सम्पादकीय

यूएस का दण्ड स्वरूप लगाया गया आयात कर लागू

भारत के उत्पादों पर अमेरिका का बुधवार यानि 27 अगस्त से 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीदने के लिए दण्ड स्वरूप लगाया आयात कर लागू हो जाएगा। इस प्रकार अब भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत आयात कर ठोक दिया है। अब अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ना तय है। यह घाटा 2024 में ही 45.8 अरब का था अब यह बढ़ सकता है। अभी तक अमेरिका में भारत का निर्यात 87 बिलियन डालर का था जो भारत की जीडीपी का 2.5 प्रतिशत था। लेकिन भारत ने अमेरिकी आयात कर के कारण विकराल चुनौती को हल करने के लिए भारत सरकार ने तत्काल चार विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है।

पहला विकल्प यह है कि भारत अमेरिका के बाहर बाजार तलाश रहा है।

कुछ दिन छोटे उद्योगों को परेशानी होनी संभव है किन्तु एक बार जब उन्हें दूसरे देशों में बाजार मिल जाएंगे तो व्यवसाय स्थिर हो जाएगा। भारत को इस बात का संदेह इस वर्ष की शुरूआत में ही हो चुका था तभी यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अप्रीकन देशों के साथ भारत ने समझौता करके आयात निर्यात के रेट तय कर लिए। दूसरा विकल्प जिसे भारत ने लागू कर दिया वह है रूस के साथ अपने व्यापार रणनीति की समीक्षा। अब भारत तेल खरीदने से आगे बढ़कर निर्यात बढ़ाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। तीसरे विकल्प के तहत अब भारत अमेरिका के खिलाफ चुनिन्दा वस्तुओं के आयात पर आयात कर में वृद्धि करने जा रहा है। पहले भारत अमेरिका के कृषि उत्पाद, फार्मास्युटिकल्स या तकनीकी उपकरणों पर आयात कर बढ़ाएगा। भारत अपने चौथे विकल्प के तहत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पर्याप्त त्रण तथा सब्सिडी देने के लिए योजना बना रहा है। इसका मतलब यह कि भारत ने अमेरिका की अनुकम्पा पर अपनी व्यापार नीति का निर्धारण न करने का दृढ़ पैसला कर लिया है। जर्मन अखबार, प्रौंक पुर्टर अल्गेमीन जेटंग ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ट्रेड टैरिफ का भारत ने सख्ती से जवाब दिया है। अखबार ने लिखा है कि इस बारे में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार कॉल किया किन्तु उन्होंने रिसीव ही नहीं किया। अखबार के मुताबिक माना जा रहा है कि भारत सरकार अब इस मामले में अमेरिका के दबाव में आने की बजाए सख्ती से जवाब देने की नीति पर विचार कर रही है। इसी पॉलिसी के तहत भारत ने चीन, रूस और ब्राजील जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया गठजोड़ खड़ा करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। शायद इसी नीति के तहत अब मोदी सरकार नहीं चाहती कि ट्रंप को ज्यादा महत्व दिया जाए। अखबार के लिए हैड्रिक अंकेनबाड, विनाडवान पीटर्स डार्प, गुस्ताव थाइले ने लिखे अपने लेख में स्पष्ट किया है कि यह भारत सरकार की बदली हुई नीति का प्रतीक है कि उसने उस चीन के साथ भी रिश्ते सामान्य करने शुरू कर दिए हैं, जिससे 2020 में लद्दाख में सैन्य झड़प हुई थी और 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसी लेख में यह भी कहा गया है कि ट्रंप टेलीफोन करके अपने मित्र देशों को धमकाते हैं और उन पर दबाव डालते हैं किन्तु भारत ने उनकी धमकी और दबाव दोनों मानने से इंकार कर दिया है। यह सच है कि जो लोग अमेरिकी टैरिफ से अर्थव्यवस्था की तस्वीर खींच रहे हैं, उनकी आशंका गलत है किन्तु अब जबकि भारत ने चीन, रूस और ब्राजील से मिलकर अमेरिका के डालर मुक्त व्यापार करने का पैसला कर लिया है तो अब उसके पीछे हटने की कोई संभावना नहीं दिखती। लब्बोलुआब यह है कि जहां अमेरिका ने भारत के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है वहीं अब उसके सारे विरोधी मिलकर ट्रंप को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमें भी वह सब कुछ करने का अधिकार है जो हमारे हित में है, भले ही उससे अमेरिका को मिर्ची लगे। सच तो यह है कि दुनिया का हर देश अमेरिका की टैरिफ की राजनीति से परेशान है और यदि एससीओ यानि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान डालर का कोई विकल्प निकला तब तो ठीक है और यदि न निकला तो भी अमेरिका विरोधी शक्तियों का विस्तार होना तय है।

दो दिवसीय वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) कार्यशाला को मुख्य अतिथि के तौर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया संबोधित

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लालकिले से कहा है कि जनसांख्यिकी में बदलाव हमारी चिंता, सीमावर्ती गाँवों के जिला कलेक्टर भी इसे जिम्मेदारी समझे

मोदी सरकार द्वारा सीमांत गांवों से पलायन रोकने और शत प्रतिशत सैचुरेशन के लिए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम की रचना हुई

शश्ठ से सीमांत गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है

जिला कलेक्टर सीमावर्ती गाँवों में उअढक्र और सेना को दूध की आपूर्ति के लिए डेयरी कोऑपरेटिव बनाएँ

सीमाएं कम से कम 30 किलोमीटर दायरे तक अतिक्रमण से मुक्त हों

अरुणाचल में शश्ठ से सरहदी गाँव में आबादी बढ़ना सारे सीमान्त गाँवों को सकारात्मक संदेश है

जिला कलेक्टर सुनिश्चित करें कि हमारे नागरिक अपना गाँव नहीं छोड़ें और गाँव की आबादी में वृद्धि भी हो

होम स्टे जैसे प्रयोगों को हर गाँव तक बढ़ाने और राज्य सरकार द्वारा बुकिंग की उचित व्यवस्था से सीमावर्ती गाँवों का एक भी घर खाली नहीं रहेगा

ढङ्गर३ीं डल्ल: 26 अवऋ् 2025 1:40ढट‚८ ढक्ह ऊ़ै

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय (टल्अ) के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (शश्ठ) कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस अवसर पर वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का लोगो भी लॉन्च किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (क्ह) के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, शश्ठ के पहले और दूसरे चरण में शामिल सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिव, सीमा की रक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के महानिदेशक और संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का विचार तीन बिंदुओं पर आधारित है, जिनमें सीमांत गांवों से पलायन रोकना, सीमांत गांवों के हर नागरिक को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना और शश्ठ में चिह्नित गांवों को सीमा और देश की सुरक्षा के लिए एक उपकरण बनाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के विचार को सामने रखा था, तब यह तय हुआ था कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। न केवल हर सीमांत गाँव को सभी सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा, बल्कि सीमांत गांवों में रहने वाले हर नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लैस करके उनके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाया जाए। साथ ही इन गांवों को देश और सीमा की सुरक्षा के मजबूत उपकरण के तौर पर विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के अंतिम गाँव को देश के पहले गाँव की उपाधि देकर सीमावर्ती गांवों को देखने का हमारा नजरिया बदलने का काम किया।

श्री अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के लिए चिह्नित किए गए देश के पहले गाँव कुछ साल बाद हमारे देश और उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मल्टी-डायमेंशनल और मल्टी-सेक्टोरल विकास की कल्पना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन और हर तरह से गाँव के जीवन को वाइब्रेंट बनाने के प्रयास हुए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, शश्ठ में शामिल गांवों के जिला कलेक्टरों और सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (उअढक्र) की जिम्मेदारी है कि वे शश्ठ तक सीमित नहीं रहें और इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह विचार करें कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम से आगे बढ़कर और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शश्ठ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी विभाग मिलकर इन सीमावर्ती गांवों को सच्चे अर्थों में सुरक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण बनाएं।

श्री अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम की संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन, पर्यटन के लिए आवश्यक जनसुविधाओं को बढ़ावा और सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर होमस्टे जैसे प्रयोगों को सीमावर्ती गांवों तक ले जाएँ और इनमें बुकिंग के लिए राज्यों के पर्यटन विभाग उचित व्यवस्था करें तो सीमांत गांवों के हर घर में रोजगार होगा। श्री शाह ने कहा कि राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग को इन गांवों का गौरव स्थापित करने की दिशा में प्रयास करना होगा और इसमें जिला कलेक्टरों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि अगर गांवों में सभी सुविधाएं और रोजगार हों तो स्थानीय लोगों में गाँव छोड़ कर जाने की इच्छा कभी नहीं होगी। गृह मंत्री ने कहा कि युवा कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद हमारे नागरिक अपना गाँव नहीं छोड़ें, पलायन न हो और गाँव की आबादी में वृद्धि भी हो।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम लागू करने के बाद कई सीमावर्ती गांवों में आबादी बढ़ी है। यह हमारे देश के सभी सीमांत गाँव के लिए एक संदेश है कि फिर से आबादी बढ़ने का हमारा यह ट्रेंड सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि डेमोग्राफिक बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम में शामिल जिलों के कलेक्टरों को इस मुद्दे को गंभीरता और बारीकी से देखना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बदलाव सीधे तौर पर देश और सीमाओं की सुरक्षा को प्रभावित करता है। गृह मंत्री ने कहा कि यह नहीं मानना चाहिए कि यह भौगोलिक स्थिति के कारण हो रहा है, बल्कि यह एक निश्चित डिजाइन के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्य सचिवों और उअढक्र को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि योजनाओं के शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लिए जिला कलेक्टरों को यह विचार करना चाहिए कि क्या वे इसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ समन्वय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में मदद प्रदान कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी ने रोजमर्रा की चीजें, जैसे - दूध, सब्जी, अंडे, अनाज आदि वाइब्रेंट गांव से ही खरीदने का सफल प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि हर सीमांत गांव में इस प्रयोग को जमीन पर उतारने की जरूरत है। श्री शाह ने यह भी कहा कि सीमा पर तैनात सेना भी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से समन्वय कर वाइब्रेंट गांव में रोजगार सृजन की जिम्मेदारी ले।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वे डेयरी कॉपरेटिव बनाकर सीएपीएफ और सेना के दूध की जरुरत को गांव से ही पूरा करे। इससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि इस प्रयोग को प्रभावी मॉडल के तौर पर विकसित कर हर वाइब्रेंट विलेज में लागू करने का काम गृह मंत्रालय, सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सेना और जिला कलेक्टरो को हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार के सृजन से पलायन अपने आप रुकेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि सीमांत गांवों में दूरसंचार, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शश्ठ को सरकारी प्रोग्राम नहीं, प्रशासन की स्पिरिट बनाना है। गृह मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकेगा, जब यह प्रशासन की स्पिरिट बनेगा। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम में मनरेगा के तहत कुछ नए तालाब बनाने, सघन वृक्षारोपण और स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-1 में हम कार्यक्रम तक सीमित रहे, लेकिन वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2 में हमें प्रशासन का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। उन्होंने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से कहा कि वे अवैध धार्मिक अतिक्रमण को हटाने की दिशा में उचित कार्रवाई करें। ये अतिक्रमण एक सुनिश्चित डिजाइन के तहत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा से कम से कम 30 किलोमीटर तक के दायरे में सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। श्री शाह ने कहा कि गुजरात ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ समुद्री और भू सीमा से ढेर सारे अतिक्रमण हटाए गए हैं।

एनएचएआई ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 'प्रोजेक्ट आरोहण' शुरू किया

(जीएनएस)।

टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएचएआई ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर 'प्रोजेक्ट आरोहण' की शुरूआत की घोषणा की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव ने नई दिल्ली स्थित एनएचएआई मुख्यालय में वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक एवं संयुक्त सीईओ डॉ. जफर खान और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना, सामाजिक-आर्थिक भेदों को कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों, जिनमें निम्न-आय वाले परिवारों की लड़कियाँ, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र शामिल हैं, के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करना है।

एसएमईसी ट्रस्ट के भारत केयर्स द्वारा कार्यान्वित 'प्रोजेक्ट आरोहण' के पहले चरण के लिए 1 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा और यह जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक चलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य कक्षा 11 से स्नातक अंतिम वर्ष तक के 500 छात्रों को शामिल करना है, जिनमें से प्रत्येक को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 12,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा के इच्छुक 50 मेधावी छात्रों को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम वित्तीय सहायता के साथ-साथ संरचित मार्गदर्शन, कौशल-निर्माण कार्यशालाओं और करियर मार्गदर्शन को भी जोड़ता है ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए समग्र रूप से तैयार किया जा सके।

इस अवसर पर एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव ने कहा, "'प्रोजेक्ट आरोहण' उन लोगों के प्रति एनएचएआई की प्रतिबद्धता को दशार्ता है जो हमारे राजमार्गों को प्रतिदिन गतिशील रखते हैं और उनके परिवारों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा और मार्गदर्शन में निवेश करके, हम ऐसी प्रतिभाओं को बढावा दे रहे हैं जो भारत के अगले दशक के विकास को गति प्रदान करेंगी।"

वर्टिस इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक और संयुक्त सीईओ, डॉ. जफर खान ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, "वर्टिस में, बुनियादी ढाँचे का निर्माण मानव क्षमता के निर्माण के साथ-साथ चलता है। प्रोजेक्ट आरोहण के माध्यम से, हमें देश के भविष्य को आकार देने में मदद करने के लिए एनएचएआई और एसएमईसी ट्रस्ट द्वारा भारत केयर्स के साथ साझेदारी करते हुए खुशी हो रही है। छात्रों की प्रतिभा को बढाने वाले मार्गदर्शन से परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में लाभ बढ़ते हैं, जिससे एक मजबूत भारत का निर्माण होता है।"

आवेदन प्रक्रिया एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्रों को शैक्षणिक रिकॉर्ड, आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, आईडी प्रमाण आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने होंगे। एक व्यवस्थित चयन प्रक्रिया छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करेगी, साथ ही दीर्घकालिक रूप से योग्य छात्रों का समर्थन करने के लिए नवीनीकरण तंत्र के साथ निरंतर मार्गदर्शन और प्रगति ट्रैकिंग भी सुनिश्चित करेगी।

यह राष्ट्रव्यापी परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा के विशाल नेटवर्क पर तैनात टोल-प्लाजा कर्मियों के समुदाय तक पहुँचेगी। अपने दूरगामी प्रभाव के साथ, 'प्रोजेक्ट आरोहण' देश भर के टोल प्लाजा कर्मचारियों के प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता, करियर जागरूकता और सुव्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

फिजी के प्रधानमंत्री ने यूआईडीएआई मुख्यालय का दौरा किया; भारत ने अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाचे की आधारशिला, आधार और कई नवीन डिजिटल समाधानों में से एक, डिजिलॉकर का प्रदर्शन किया

भारत ने समावेशी डिजिटल शासन के माध्यम से बड़े पैमाने पर सेवा प्रदान करके निवासियों को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला

(जीएनएस)।

फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री सिटिवेनी लिगाममादा राबुका ने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्यालय का दौरा किया। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री भुवनेश कुमार और विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस दौरान, फिजी के प्रधानमंत्री को भारत की अग्रणी डिजिटल पहचान प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की आधारशिला है।

यूआईडीएआई के उप महानिदेशक श्री विवेक चंद्र वर्मा और एनईजीडी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नंद कुमारम ने आधार और डिजिलॉकर पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं और निवासियों को सशक्त बनाने तथा समावेशी डिजिटल शासन को सक्षम बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन और सेवा वितरण को सक्षम बनाने में उनके डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभाव का उल्लेख किया।

प्रतिनिधिमंडल ने आधार नामांकन प्रक्रिया का सजीव प्रदर्शन भी देखा, जिससे उन्हें भारत के डिजिटल पहचान व्यवस्था की सहजता, पैमाने, दक्षता और सुरक्षा के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई।

यह दौरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में भारत और फिजी के बीच बढ़ते सहयोग को दशार्ती है, जिसमें नवीन डिजिटल परिवर्तनकारी समाधानों के विकास में सहयोग भी शामिल है। यह वैश्विक भागीदारों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपनी विशेषज्ञता साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

सोने के छोटे कण पार्किंसंस रोग का शीघ्र पता लगाने में मदद कर सकते हैं

पीली धातु, अर्थात इसके सूक्ष्म कण, पार्किंसंस रोग (पीडी) का शीघ्र पता लगाने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण की कुंजी बन सकते हैं।

पार्किंसंस रोग दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते तंत्रिका संबंधी विकारों में से एक है। बढ़ती उम्रदराज आबादी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ, भारत में इस रोग से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ेगा। फिर भी, ज्यादातर निदान तभी होते हैं जब गंभीर तंत्रिका क्षय पहले ही हो चुका होता है।

इसलिए शोधकर्ता ऐसे तरीकों की तलाश में हैं जिनसे रोग का प्रारंभिक चरण में ही पता लगाया जा सके ताकि इसके उचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त उपाय किए जा सकें।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली के वैज्ञानिकों के बीच एक समूह चर्चा में, जिसमें यह पता लगाया जा रहा था कि बीमारी के दौरान मस्तिष्क में प्रोटीन किस तरह अलग तरह से व्यवहार करते हैं, एक बड़ा विचार सामने आया। उन्होंने यह पता लगाना शुरू किया कि क्या वे किसी प्रोटीन की सतह पर मौजूद आवेश को महसूस करके उसकी खतरनाक स्थिति का पता लगा सकते हैं।

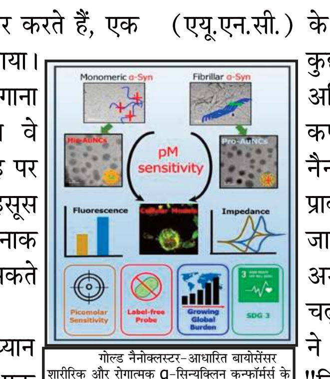

गोल्ड नैनोक्लस्टर-आधारित बायोसेंसर शारीरिक और रोगात्मक α-सिन्यूक्लिन कन्फॉर्मर्स के बीच अंतर करता है, जिससे पार्किंसंस रोग का प्रारंभिक चरण में पता लगाना संभव हो जाता है।

उन्होंने अपना ध्यान α-सिन्यूक्लिन नामक एक प्रोटीन पर केंद्रित किया जो पीडी से जुड़ा है। यह प्रोटीन आकार बदलता है, शुरूआत में हानिरहित होता है, और अंततः विषाक्त रूपों में परिवर्तित होकर मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाता है। टीम ने एक ऐसे सेंसर पर काम करना शुरू किया जो इन प्रोटीन रूपों को उनके आवेशित होने के आधार पर ही अलग-अलग पहचान सके।

आईएनएसटी

उनका समाधान स्वर्ण नैनोक्लस्टर्स (एयू.एन.सी.) के रूप में आया, जो कुछ नैनोमीटर चौड़े, अतिसूक्ष्म, चमकते कण थे। इन नैनोक्लस्टर्स पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की परत चढ़ाकर, शोधकर्ताओं ने उन्हें चयनात्मक "चिपचिपापन" प्रदान किया। प्रोलाइन-लेपित क्लस्टर्स प्रोटीन के सामान्य रूप की ओर आकर्षित हुए, जबकि हिस्टिडीन-लेपित क्लस्टर्स विषाक्त समुच्चयों से चिपक गए। इससे हानिरहित मोनोमेरिक रूप और विषाक्त समुच्चय (एमिलॉइड) रूप के बीच अंतर करने में मदद मिली।

अवधारणा से सिद्धांत तक की यात्रा में प्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। टीम ने α-सिन्यूक्लिन प्रोटीन (सामान्य और उत्परिवर्ती) के दो रूपों की इंजीनियरिंग और शुद्धिकरण से शुरूआत की। फिर उन्होंने अमीनो अम्ल-आवरण वाले स्वर्ण नैनोक्लस्टर्स को संश्लेषित किया और उनके प्रकाशीय और संरचनात्मक गुणों को समझने के लिए यूवी-विज स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रतिदीप्ति इमेजिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टी.ई.एम.) और एक्स-रे फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी (एक्स.पी.एस.) जैसी उच्च-स्तरीय तकनीकों का उपयोग करके उनका सावधानीपूर्वक लक्षण-निर्धारण किया। नैनोक्लस्टर्स और प्रोटीन के बीच की अंतःक्रियाओं का अध्ययन जेल वैद्युतकणसंचलन, प्रतिदीप्ति शमन, और चक्रीय वोल्टमेट्री और प्रतिबाधा स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी विद्युत-रासायनिक विधियों के माध्यम से किया गया।

आत्मनिर्भरता और एकीकृत लॉजिस्टिक्स के बल पर सभी क्षेत्रों में निर्णायक संयुक्त प्रतिक्रियाएं भविष्य के युद्धों में जीत की कुंजी होंगी: रण संवाद में सीडीएस

(जीएनएस)।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्धों में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में त्वरित और निर्णायक संयुक्त प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धक्षेत्र, सेवा सीमाओं को नहीं पहचानेंगे। जनरल अनिल चौहान, 26 अगस्त, 2025 को मध्य प्रदेश के डॉ. अंबेडकर नगर स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में 'युद्ध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव' विषय पर युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर अपनी तरह के पहले त्रि-सेवा सेमिनार, 'रण संवाद' में मुख्य भाषण दे रहे थे।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और एकीकृत लॉजिस्टिक्स को आगामी युद्धों में विजयी होने की कुंजी बताते हुए सीडीएस ने दोहराया कि 'संयुक्तता' भारत के परिवर्तन का आधार है। उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और क्वांटम जैसी निरंतर विकसित हो रही तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। एक मजबूत नागरिक-सैन्य एकीकरण के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र (भारत का अपना लौह गुंबद) विकसित करने के महत्व और प्रतिबद्धता पर बल दिया जो 'ढाल और तलवार' दोनों का काम करेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताओं का विकास आवश्यक है।

जनरल अनिल चौहान ने कौटिल्य का हवाला देते हुए कहा कि भारत प्राचीन काल से ही विचारों और ज्ञान का स्रोत रहा है। हालांकि, भारतीय युद्धों के विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण या रणनीति पर अकादमिक चर्चा का बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि युद्ध, नेतृत्व, प्रेरणा, मनोबल और तकनीक के विभिन्न आयामों पर गंभीर शोध किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित बनना होगा और यह तभी संभव है जब सभी हितधारक भविष्य के लिए तैयार सेनाओं के निर्माण में सामूहिक रूप से भाग लें।

सीडीएस ने बताया कि रण संवाद का उद्देश्य वास्तविक अभ्यासकताओं के लिए एक मंच तैयार करना है, विशेष रूप से युवा और मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए जो तकनीकी प्रगति से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि उनके विचारों को सुनने की आवश्यकता है ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जहां नए विचारों के बीच सामंजस्य और सद्भाव, सैन्य-कर्मियों द्वारा प्रदान किए गए अनुभव के साथ सह-अस्तित्व में रह सके।

दो दिवसीय संगोष्ठी में सेवारत सैन्य पेशेवरों को रणनीतिक संवाद के अग्रभाग में लाया जाएगा।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

पश्चिम रेलवे द्वारा 15 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

मुंबई,
पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मौजूदा संरचना, पथ और समय पर 15 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम स्पेशल को 31 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम–मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 1 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल–कानपुर अनवरगंज स्पेशल को 28 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज–मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09043 बांद्रा टर्मिनस–बढ़नी स्पेशल को 28 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09044 बढ़नी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

4. ट्रेन संख्या 02200 बांद्रा टर्मिनस – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट स्पेशल को 27 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल को 25 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

5. ट्रेन संख्या 04126 बांद्रा टर्मिनस – सूबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल को 30 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04125 सूबेदारगंज – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

6. ट्रेन संख्या 04156 उधना – सूबेदारगंज स्पेशल को 30 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04155 सूबेदारगंज – उधना स्पेशल को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

7. ट्रेन संख्या 09025 वलसाड–दानापुर स्पेशल 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09026 दानापुर – वलसाड स्पेशल को 30 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

8. ट्रेन संख्या 09007 वलसाड – खातीपुरा स्पेशल को 30 अक्टूबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09008 खातीपुरा – वलसाड स्पेशल को 31 अक्टूबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

9. ट्रेन संख्या 09059 उधना – खुर्दा रोड स्पेशल को 31 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09060 खुर्दा रोड – उधना स्पेशल को 2 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

10. ट्रेन संख्या 09117 उधना – सूबेदारगंज स्पेशल को 26 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09118 सूबेदारगंज–उधना स्पेशल को 27 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

11. ट्रेन संख्या 09039 उधना–धनबाद स्पेशल को 26 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09040 धनबाद–उधना स्पेशल को 28 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

12. ट्रेन संख्या 09031 उधना–जयनगर स्पेशल को 28 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09032 जयनगर–उधना स्पेशल को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

13. ट्रेन संख्या 09045 उधना–पटना स्पेशल को 26 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09046 पटना–उधना स्पेशल को 27 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

14. ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा–मऊ स्पेशल को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09196 मऊ – वडोदरा स्पेशल को 30 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

15. ट्रेन संख्या 09343 डॉ. अंबेडकर नगर – पटना स्पेशल को 25 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09344 पटना – डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल को 26 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09075, 09185, 09043, 02200, 04126, 09156, 09025, 09007, 09059, 09117, 09039, 09031, 09045, 09195 एवं 09343 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 28 अगस्त, 2025 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

29 अगस्त से 5 सितंबर तक गांधीनगर यार्ड और जीईबी पावरप्लांट के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 5 बंद रहेगा

अहमदाबाद मण्डल पर गांधीनगर यार्ड और गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (GEB) पावरप्लांट के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 5 जीईबी गेट, डब्ल्यू पोस्ट नं 05/04-05 अति आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के लिए 29 अगस्त 2025 को प्रातः 09.00 बजे से 5 सितंबर 2025 को 18.00 तक (कुल 8 दिन) बंद रहेगा। सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेलवे क्रॉसिंग नं. 4 जीईबी गेट, OHE पोस्ट नं GEB-03/16-17 से आवागमन कर सकते है।

30 सितंबर तक तलोद-रखियाल रेलखंड में स्थित अंडरपास (आरयूबी) नं. 43ए बंद रहेगा

अहमदाबाद मंडल के असारवा–हिम्मतनगर सेक्शन के तलोद–रखियाल रेलखंड में स्थित रेलवे अंडरपास (RUB) नं. 43A, (LC-48) किमी 360/2-3 (खेरोल रोड) मानसून सीजन में जल भराव की समस्या को देखते हुए 30 सितंबर 2025 तक आवागमन हेतु बंद रहेगा।

वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति को को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सुचारु व सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश से इस अंडरपास (RUBs) को बंद रखा गया है।

पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती-कटोसन रोड के बीच मेमू ट्रेन की शुरूआत

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए साबरमती और कटोसन रोड के बीच यात्री ट्रेन सेवा (मेमू ट्रेन) की शुरूआत की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- साबरमती–कटोसन रोड मेमू ट्रेन (शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन)

ट्रेन संख्या 69249 साबरमती–कटोसन रोड मेमू साबरमती से 06.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा 08.05 बजे कटोसन रोड पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 69250 कटोसन रोडइ साबरमती मेमू कटोसन रोड से 19.05 बजे प्रस्थान करेगी तथा 20.30 बजे साबरमती पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में कलोल, कड़ी और भोयनी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 8 कोच रहेंगे। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा वडोदरा - मऊ स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए वडोदरा मण्डल से चलने वाली वडोदरा झ मऊ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विशेष किराये पर समान संरचना,समय, ठहराव तथा मार्ग पर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

* ट्रेन नंबर 09195/09196 वडोदरा – मऊ स्पेशल

ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा – मऊ स्पेशल जिसे पहले 29 सितंबर 2025,तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 29 दिसम्बर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09196 मऊ – वडोदरा स्पेशल जिसे पहले 30 सितंबर, 2025 अब उसे 30 दिसम्बर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन नंबर 09195 की विस्तारित फेरों की बुकिंग 28 अगस्त, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेन के ठहराव, संरचना के समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ब्लॉक प्रमुख ने 21छात्रों को बांटे टैबलेट, दी सीख किताबों से निकलकर अब शिक्षा टैबलेट पर जाएगी, तकनीक संग नई ऊँचाइयाँ पाएगी

(जीएनएस) ।
भरावन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अतरौली में मंगलवार को प्रज्ञा सिंह, कौशलेंद्र पाल,मुकेश कुमार,उपेंद्र सिंह, आस्था सिंहसीमा तिवारी प्रशांत वर्मा शालू सिंह सुमित कुमार लालू कुमार उत्तम पाल किरण देवी अंकित रजनी देवी सहित कुल 21 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए।ये प्रशिक्षणार्थी मैकेनिक (आरएसी), इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कॉस्मेटोलॉजी और मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से जुड़े हैं।इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह तोमर ने कहा कि विद्यार्थी टैबलेट का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं।आज के समय में युवा डिजिटल उपकरणों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जबकि सरकार का उद्देश्य इन्हें शिक्षा और करियर निर्माण का सशक्त माध्यम बनाना है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को युवाओं के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि छात्र–छात्राएँ डिजिटल युग में अपनी अलग पहचान बनाकर सफलता की नई ऊँचाइयों को छुएँ। संस्थान के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार मिश्रा ने सरकार की इस पहल को विद्यार्थियों को डिजिटल ज्ञान देने की दिशा में सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम में कार्यदेशक अब्दुल राफे, राजेश कुमार विनोद कुमार, विभा, अब्दुल मुतालिफ खान, यथार्थ मिश्रा,दिलीप कुमार,जितेंद्र सिंह,संजय कुमार, दीपेंद्र सिंह,अमित गुप्ता , कविता ,पल्लवी विश्वकर्मा,पुष्पलता, आकर्षित रहे।

विशाल भंडारा काली के मंदिर पर भक्तों की उमड़ी भारी भीड़

(जीएनएस) ।
बिजनोर क्षेत्र स्योहारा मुरादाबाद रोड पर स्थित प्राचीन काली का मंदिर में आज एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। पूरे दिन जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। यह संयोजक अतुल जोशी, प्रमोद जोशी पूर्व बाबू नगर पालिका स्योहारा,बड़े, अंकुल जोशी, उषा जोशी,पूजा जोशी,पूनम जोशी, सालनि जोशी,रीता जोशी,अर्चना जोशी,उमंग जोशी, काना जोशी, कनिका जोशी, व परिवार के सहयोग से आयोजित किया गया था। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। दूर-दूर से आए भक्तों ने मां काली के दर्शन किए और पूजा-अर्चना में भाग लिया।भंडारे में पूड़ी, सब्जी, हलवा और अन्य पकवान बनाए गए थे, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी ने बड़े उत्साह के साथ भंडारे का आनंद लिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि यह आयोजन हर साल किया जाता है और इसमें सभी धर्मों के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं।भंडारे को सफल बनाने में स्थानीय पुलिस और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने के कारण किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। भक्तों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रसाद ग्रहण किया जिसके बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ।

2025 से प्रतिवर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा

(जीएनएस)।
भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में जारी एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है कि वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार, आयुर्वेद दिवस हर वर्ष एक निश्चित तिथि अर्थात 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इससे पहले, आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती (धनतेरस) को मनाया जाता था। इस निश्चित तिथि निर्धारित करने का निर्णय एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो आयुर्वेद को एक सार्वभौमिक कैलेंडर पहचान प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर इसकी व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाता है।

इस वर्ष के उत्सव का विषय- 'लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद' की घोषणा करते हुए, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि आयुर्वेद केवल एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित जीवन का विज्ञान है। 23 सितंबर को आयुर्वेद

दिवस के रूप में घोषणा के साथ, भारत ने आयुर्वेद को एक वैश्विक कैलेंडर पहचान दी है। 2025 का विषय 'लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद' वैश्विक कल्याण और एक स्वस्थ ग्रह के लिए आयुर्वेद की पूरी क्षमता का दोहन करने के हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि 2016 में अपनी स्थापना के बाद से, आयुर्वेद दिवस भारत के पारंपरिक ज्ञान का उत्सव मनाने वाले एक वैश्विक आंदोलन के रूप में उभरा है। प्रथम अखिल भारतीय एनएसएसओ सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि आयुर्वेद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली उपचार प्रणाली है। 2025 का विषय समग्र स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी संतुलन को आगे बढ़ाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

9वां आयुर्वेद दिवस (2024) भारत की स्वास्थ्य सेवा यात्रा में एक उपलब्धि रहा है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, आयुर्वेद में चार उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया और लगभग 12,850 करोड़ रुपये की लागत वाली अन्य स्वास्थ्य संबंधी पहलों के साथ-साथ राष्ट्रव्यापी "देश का प्रकृति परीक्षण अभियान" का शुभारंभ किया। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, आयुर्वेद दिवस 2025 को केवल एक औपचारिक अवसर के रूप में नहीं, बल्कि आयुर्वेद को समकालीन वैश्विक चुनौतियों जैसे जीवनशैली संबंधी विकार, जलवायु से जुड़े रोग और तनाव प्रबंधन के समाधान के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पैमेंट्स बैंक की प्रगति की समीक्षा की

उल्लेखनीय वृद्धि: 12 करोड़ ग्राहक, 20,000 करोड़ रुपये जमा राशि और लाभप्रद संचालन

इंडिया पोस्ट और आईपीपीबी अंतिम-छोर तक बैंकिंग सेवा पहुंचा रहे हैं: डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी

(जीएनएस)।
केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पैमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के प्रदर्शन की समीक्षा की। चर्चा का केंद्र डिजिटल पहल, उपभोक्ता सुविधा और सेवाओं को देशभर में अधिक सुलभ बनाने के उपाय रहे।

श्री पेम्मासानी ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया पोस्ट और आईपीपीबी

के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों को, उनके द्वार पर ही सस्ती और भरोसेमंद सेवाएं मिलती रहें। उन्होंने रेखांकित किया कि विश्वास, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवाओं को पहुंचाना प्रमुख प्राथमिकताएं बनी हुई हैं।

केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पैमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के प्रदर्शन की समीक्षा की।

प्रदर्शन की अद्यतन स्थिति

अधिकारियों ने श्री पेम्मासानी को बताया कि हाल के वर्षों में आईपीपीबी ने तेजी से विस्तार किया है। 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जमा राशि, 2,200 करोड़ रुपए के राजस्व और 134 करोड़ रुपए के लाभ के साथ, बैंक ने पिछले दो वर्षों में 60–70 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है।

इस क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद, आईपीपीबी ने ये वृद्धि लगभग 1,250 कर्मचारियों की छोटी और इंडिया पोस्ट की बेजोड़ पहुंच के बल पर

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं नागरिकों को जागरूक करने हेतु साइबर जागरूकता अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है

(जीएनएस) ।
गाजियाबाद श्रीमती प्रियाश्री पाल, सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी, थाना प्रभारी वेवसिटी व पुलिस टीम द्वारा थाना वेवसिटी क्षेत्रान्तर्गत स्थित रॉयल कॉलेज आफ लॉ के ऑडिटोरियम में एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के चेयरमैन श्री विजय अग्रवाल, प्रिंसिपल डॉक्टर टीना गर्ग, छात्र-छात्राएं व अन्य गण मान्य लोग उपस्थित रहे। जिसमें आधुनिक साइबर अपराधों की

पहचान करने, संभावित खतरों से स्वयं को सुरक्षित रखने तथा साइबर सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता का प्रसार करने हेतु जागरूक किया गया। उक्त कार्यक्रम में शिक्षार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य नागरिकों को बताया गया कि किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें ।

राजनगर एक्सटेंशन की सडकों से हटाया अतिक्रमण

(जीएनएस) ।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के दिए गए आदेशों के क्रम में आज दिनांक 26 अगस्त 2025 को प्राधिकरण के जोन–01 के अंतर्गत आने वाले राजनगर एक्सटेंशन की 45, 30 मीटर एवं अन्य चौड़ी सड़कों से प्राधिकरण के प्रवर्तन और अभियंत्रण अनुभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ज्योति सुपर के गेट के सामने टीन शेड डाल कर प्रसादम भोजनालय के नाम से अतिक्रमण किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक रेहडी पटरी वालों को भी हटाया गया। प्रवर्तन प्रभारी ने इस दौरान चेतावनी दी कि भविष्य में पुनः रोड पटरी आदि पर किसी तरह का अतिक्रमण किया जाता है तो कडी कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्यवाही अभियंत्रण एवं प्रवर्तन के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ। कार्यवाही के समय अभियंत्रण और प्रवर्तन जोन-01 के तमाम स्टाफ के साथ प्राधिकरण का तमाम पुलिस बल स्टाफ और स्थानीय थाना पुलिस बल भी उपस्थित रहा ।

जीतू पटवारी का दावा: म.प्र. की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, जानिए पूरा सच, एनएफएचएस रिपोर्ट का खुलासा

(जीएनएस)।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के चीफ जीतू पटवारी का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं"। यह बयान उन्होंने राज्य की इखढ सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे मुद्दों पर हमला बोलते हुए दिया।

पटवारी ने कहा कि इखढ ने समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना दिखाया, लेकिन हकीकत में महिलाओं को नशे की लत लग गई है। इस बयान ने सियासी हलकों में तूफान मचा दिया है–कुछ लोग इसे इखढ सरकार की नाकामी का प्रमाण बता रहे हैं, तो कुछ इसे सियासी बयानबाजी करार दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई टढ की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं? हमने NFHS-5 और अन्य रिपोर्ट्स की पड़ताल की, और जो सच निकला, वह चौंकाने वाला है। आइए, इस बयान की हकीकत पर गहराई से नजर डालते हैं।

जीतू पटवारी का बयान: सरकार पर नशे का आरोप

जीतू पटवारी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इखढ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना दिखाने वाली इखढ ने यह हालत कर दिए हैं, जितना ड्रग का कारोबार यहां होता है उतना दूसरी किसी राज्य में नहीं होता। मुख्यमंत्री ने यह प्रयास नहीं किए कि इससे निजात कैसे दिलाएं। हमारी बहनें, बेटियां नशा करने लगी हैं, लाडली बहना के नाम पर वोट तो ले लिए और मध्य प्रदेश में बहना ही सबसे ज्यादा नशा करती हैं। इस पर विचार करना चाहिए।"

NFHS-5 रिपोर्ट का खुलासा: टढ की महिलाएं शराब से दूर

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) भारत में अल्कोहल कंजम्पशन के सबसे विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं में अल्कोहल कंजम्पशन का राष्ट्रीय औसत मात्र 0.7% है। लेकिन राज्यवार आंकड़े देखें, तो टढ की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली नहीं हैं–बल्कि सबसे कम पीने वाली राज्यों में शुमार हैं।

भारत सरकार की "सोशल जस्टिस मंत्रालय की रिपोर्ट, 2019) के अनुसार, देशभर में करीब 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब पीने वालों में महिलाओं की संख्या बेहद कम है – महज 1.6%। राज्यों की लिस्ट में मध्य प्रदेश शीर्ष पर नहीं है। सर्वे के मुताबिक, पूर्वोत्तर के राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और असम – में महिलाओं के शराब पीने का प्रतिशत सबसे ज्यादा है।

लोगों ने सुबह से शाम तक लगाई दौड़ फिर भी नहीं मिली खाद

(जीएनएस)।
जनपद हरदोई विकास खड़ं भरावन गोड़वा समिति मे खाद भंडार मे लोगो की लगी भीड़ गोड़वा के सच्चीव सुरेश और मंडल अध्यक्ष अमन और संजय और शिवा लेकपाल और अतरौली थाने की पुलिस दर्मेंद्र कुमार एसा ई और सिपाही सरकारी कर्मचारी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं 265 की खाद बोरी वितारित कर रहे हैं संडीला ब्लॉक और भरावन ब्लॉक और कोथावा ब्लॉक के लोग खाद के चक्कर में लोग हो रहे हैं परेशान खाद न मिलने पर लोग कर रहे हैं मारा-मारी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कथित तौर पर तीन श्रमिकों की मृत्यु के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया

(जीएनएस)।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मीडिया में आई उन खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें बताया गया था कि 20 अगस्त, 2025 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में निमार्णाधीन चार मंजिला भवन का एक हिस्सा गिरने से तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई और कई अन्य बाल-बाल बच गए। सभी मृतक बिहार के प्रवासी श्रमिक थे। आयोग ने समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु की जांच की है और कहा है कि यदि यह जानकारी सही है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। तदनुसार, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

मुंबई पुलिस का बड़ा अभियान, 64 दिनों में चोरी हुए 8000 मोबाइल फोन लोगों को लौटाए

(जीएनएस)।
मुंबई पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. पुलिस ने 64 दिनों में 8000 मोबाइल फोन वापस किए हैं. (आज तक रिपोर्ट के मुताबिक) दूरसंचार विभाग का केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (उएक्क्र) और थानों पर तैनात अधिकारियों की कड़ी मेहनत की वजह से यह संभव हो पाया.इस अभियान की निगरानी खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे थे. मुंबई पुलिस ने इस साल जून महीने में शहर भर में चोरी हुए मोबाइल फोन वापस

करने पर प्राथमिकता और ध्यान केंद्रित करते हुए एक अभियान शुरू किया था. इस साल 18 जून से 21 अगस्त तक, यानी सिर्फ.दो महीनों में 8000 से ज्यादा मोबाइल फोन विभिन्न पुलिस थानों और फिर उनके मालिकों को वापस किए गए हैं.

यह आंकड़ा दशार्ता है कि औसतन प्रतिदिन लगभग 125 मोबाइल फोन वापस किए गए और बरामद किए गए। क्टएक के जरिए मोबाइल फोन को ट्रैक करने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन अब दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (उएक्क्र) चोरी हुए मोबाइल फोनों को लगातार ट्रैक करने में मदद कर रही है, चाहे वे राज्य के भीतर हों या दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किए जा रहे हों.

जुलाई से मुंबई के विभिन्न पुलिस थानों में विशेष आयोजन हुए हैं, जहां सैकड़ों मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस लौटाए गए हैं, जिन्हें ये फोन 'गलती से मिले' थे या किसी ने उन्हें बिना यह जाने कि ये चोरी हुए हैंडसेट हैं, बेच दिए थे.

तालाब का पानी बना ग्रामीणों का कहर

घरों के अंदर पानी ने किया अपना प्रवेश तथा ग्रामीणों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त गांव के

लोगों ने अपनी परेशानियों को लेकर उच्च अधिकारियों का लगा रहे चक्कर लेकिन नहीं मिला उन्हें न्याय

(जीएनएस)।
26 अगस्त सन 2025 को थाना थरियांव क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम आशिकपुर औरैया में गांव के अन्दर बना तालाब जिसका गाटा संख्या 568/1.2650 हे0 का ओम प्रकाश २/0 सहदेव ने मछरी पालन हेतु तालाब का पट्टा करवाया था जिससे की बरसात का पानी भरा ही रहता है तथा हमारे गांव का दबंग व्यक्ति ओमप्रकाश २/0 सहदेव अपनी दबंगई दिखाते हुए जबरन अपने समरसेबल से तालाब में पानी छोड़ता है जिससे कि अधिक जल भराव होने के कारण तालाब का पानी ग्रामीणों के घरों के अंदर प्रवेश कर लिया है जिससे कि उनको आने-जाने में व बैठने उठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिससे कि ग्रामीण परेशान होकर ओम प्रकाशव को मना किया तो मार पीट व गाली गलौज करते हुए उनको वहां से भगा देता है और कहता है कि जो तुमको करना है वो कर लेना तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे और ज्यादा बकवास करोगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा तथा इसी के साथ ही साथ बताते चलें कि परेशान ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फतेहपुर को ज्ञापन देते हुए समस्या को बताया तथा ग्रामीणों ने कहा कि यदि उच्च स्तरीय जांच नहीं की गई तो प्रथिगणों के मकान गिर जाएंगे जिससे कि उनके जीवन काल में अंधेरा छा जाएगा तथा ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व टीम एक बार हमारे ग्राम में आकर सही ढंग से इसकी जांच कर उचित कार्यवाही करें ताकि लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त होने से बच सके। तथा ओमप्रकाश २/0 सहदेव निवासी आशिकपुर औरैया थाना थरियांव जिला फतेहपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गाटा संख्या 568 का पट्टा निरस्त किए जाने का आदेश करें ताकि प्रथिगण अपनी समस्या से निजाद पा सके। आईए सुनते हैं बाइट के माध्यम से ग्रामीणों की जुबानी।

आखिर क्यों विस्थापित की गई साईं बाबा की प्रतिमा? पुजारी और श्रद्धालुओं ने बताई बड़ी बात

(जीएनएस)।
यूपी संभल जिले के मोहल्ला ठेर स्थित शिव मंदिर में बड़ा धार्मिक बदलाव देखने को मिला। यहां वर्षों से स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा को हटाकर गंगा में विसर्जित कर दिया गया। मंदिर समिति ने अब 27 अगस्त को गणेश प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है।

स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि धीरे-धीरे लोगों का साईं बाबा की पूजा से मोहभंग होने लगा था। मंदिर पुजारी सहित भक्तों ने सामूहिक बैठक कर सहमति बनाई और प्रतिमा विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की। विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

मंदिर का निर्माण वर्ष 1992 में

हुआ था और तभी से शिवलिंग की नियमित पूजा होती आ रही है। वर्ष 2011 में एक परिवार ने अपनी माताजी की स्मृति में यहां साईं बाबा की प्रतिमा लगवाई थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में उनकी पूजा में आस्था कम हो गई थी।

गंगा में किया गया विधिवत विसर्जन

प्रतिमा हटाने का काम रविवार से शुरू कर दिया गया था। पहले प्रतिमा के चारों ओर लगी सुरक्षा रेलिंग और प्लाई हटा दी गई। इसके बाद मंगलवार सुबह साईं बाबा की प्रतिमा को उठाकर अनूपशहर गंगा ले जाया गया और विधि-विधान से विसर्जन किया गया।

श्रद्धालुओं का कहना है कि यह निर्णय विवाद टालने और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप लिया गया। सभी भक्त गंगा तट पर इकट्ठा हुए और सामूहिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का जल समर्पण किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा।

गणेश प्रतिमा स्थापना की तैयारियां

मंदिर के पुजारी आचार्य अवनीश शास्त्री ने बताया कि अब 27 अगस्त को गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर विशेष पूजन, हवन और आरती का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं का मानना है कि इससे मंदिर का धार्मिक वातावरण और भी पवित्र होगा।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि गणेश प्रतिमा की स्थापना गणेश चतुर्थी से पहले होना शुभ संयोग है। समिति ने तैयारी शुरू कर दी है और भक्त बड़ी संख्या में इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद जता रहे हैं।

मामले पर आई श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया

मोहल्ले के निवासी कमलकांत तिवारी ने बताया कि साईं बाबा की प्रतिमा का विसर्जन सर्वसम्मति से किया गया है। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सभी ने माना कि जब श्रद्धा नहीं रही तो प्रतिमा को विस्थापित कर गंगा में प्रवाहित करना उचित था।

अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से किसी की भावनाएं आहत नहीं हुईं। सभी ने शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराया। श्रद्धालु अब नई गणेश प्रतिमा के स्वागत को लेकर उत्साहित हैं और मंदिर में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।

पंडित अवनीश शास्त्री ने बताया कि वेदों और पुराणों में साईं बाबा की पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए सनातन परंपरा के अनुरूप उन्हें मंदिर से हटाया गया। यह निर्णय शास्त्रसम्मत मान्यताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।

'आलम साहब की कृपा से मेरी बेल अर्जी 2 साल चली', कौन हैं रउ के जज आफताब आलम? जिनका जिक्र अमित शाह ने किया

(जीएनएस)।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल पर बहस के दौरान अपने पुराने दिनों की यादें ताजा कीं। इस बिल में प्रावधान है कि अगर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए और वह 30 दिनों के भीतर जमानत हासिल नहीं कर पाता, तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा।

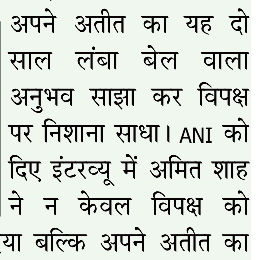

आज जब अमित शाह संविधान संशोधन बिल लाकर मंत्रियों को जेल में रहकर शासन करने से रोकने की बात कर रहे हैं, उसी बहस में उन्होंने अपने अतीत का यह दो साल लंबा बेल वाला अनुभव साझा कर विपक्ष पर निशाना साधा। ANI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने न केवल विपक्ष को जवाब दिया बल्कि अपने अतीत का एक ऐसा वाकया भी सुनाया जिसने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के जज आफताब आलम का नाम सुर्खियों में ला दिया।

अमीत साटम मुंबई भाजपा के नए अध्यक्ष नियुक्त; बीएमसी चुनावों से पहले फडणवीस का एलान

(जीएनएस)।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बताया कि तीन बार विधायक रहे अमीत साटम को मुंबई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह घटनाक्रम इस साल के अंत में होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनावों से पहले हुआ है।फडणवीस ने उम्मीद जताई कि साटम के नेतृत्व में भाजपा बीएमसी में फिर से सत्ता हासिल करेगी। 49 वर्षीय साटम लगातार तीन बार मुंबई के अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

'मुंबई इकाई के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति जरूरी थी'

राज्य भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने (निवर्तमान) नगर इकाई प्रमुख आशीष शेलार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की और मुंबई में अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने कहा, 'शेलार की ओर से कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाले जाने के बाद मुंबई इकाई के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति जरूरी थी। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में राज्य स्तर पर हुई चर्चा के बाद अमित साटम को इस पद के लिए चुना गया है।'

'विद्वान और दृढ़निश्चयी विधायक के रूप में जाना जाता है'

मुख्यमंत्री ने कहा कि साटम लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। उन्होंने कहा, 'उन्हें एक विद्वान और दृढ़निश्चयी विधायक के रूप में जाना जाता है। साटम मुंबई के ज्वलंत मुद्दों से परिचित हैं और उन्होंने उनसे निपटने के लिए आवश्यक कौशल का प्रदर्शन किया है।'

'नगर निकाय चुनावों में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी इखढ'

फडणवीस ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भाजपा आगामी नगर निगम चुनावों में अपनी जीत की लय बनाए रखेगी और मुझे विश्वास है कि हम बीएमसी में फिर से सत्ता हासिल करेंगे।' मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुंबई और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से उन्हें उम्मीद है

पर्यटन वाहन स्वामी 28 अगस्त को करेगे पीएमओ वाराणसी घेराव: राकेश कुमार सिंह।

(जीएनएस)।
वाराणसी आज दिनांक 26 अगस्त 2025 को बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन बी टी टी ए तथा सभी छोटे बड़े वाहन मालिक संघ टेंपो ट्रैवलर मिनी बस कार स्वामी संगठन की संयुक्त बैठक मिंट हाउस स्थित होटल में संपन्न हुई।

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार बॉर्डर पर हो रही जबरन वसूली और अवैध चालान अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीटीटीए अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा यदि बिहार सरकार ने इस गंभीर समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया तो देशभर के टूरिस्ट वाहन स्वामी 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय पी एम ओ का घेराव करेंगे। इसके साथ ही यदि हमारी मांगों को अनसुना किया गया तो सभी प्रांतों के पर्यटक वाहन स्वामी अनिश्चितकालीन अवधि के लिए अपनी सेवाएँ पूरी तरह बंद कर देंगे जिससे पूरे देश की पर्यटन व्यवस्था ठप हो जाएगी।

महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि

यदि बिहार मध्य प्रदेश जैसे तमाम स्टेट में अवैध टैक्स वसूली के नाम पर वाहनों के चालान करना जैसे दमनकारी कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर और भी व्यापक रूप से किया जायेगा आज छोटी बड़ी तमाम टूरिस्ट वाहन स्वामियों ने यहां पर उपस्तिथि होकर आंदोलन का समर्थन व संकल्प लिया जिसमें बतौर छोटी बड़ी वाहनों के अध्यक्ष गण एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे बैठक में उपस्थित सर्वश्री विनोद कुमार सिंह शशि प्रताप सिंह प्रकाश जायसवाल सुनील सिंह माया सिंह बंटी सिंह हर्षवर्धन सिंह रोहित सिंह बृजेश यादव अवनीश मिश्रा शैलेंद्र त्रिपाठी पप्पू यादव प्रदीप सिंह बच्चा रजनीश दुबे आनंद सिंह बिहारी पांडे अमित शुक्ला विजय सिंह रजत सिंह नीरज बादलानी सहित तमाम ट्रांसपोर्टर साथी उपस्थित रहे।

सेल ने आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि के लिए क्रिटिकल -ग्रेड स्टील की आपूर्ति करके देश के रक्षा क्षेत्र के साथ अपनी साझेदारी जारी रखी

(जीएनएस)।
भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक और महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (रअक्छ), ने भारतीय नौसेना के दो उन्नत फ्रंटलाइन युद्धपोतों, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि के लिए लगभग 8,000 टन क्रिटिकल-ग्रेड स्टील की आपूर्ति करके देश के रक्षा क्षेत्र के साथ अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी जारी रखी है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, विशाखापत्तनम में, आयोजित एक समारोह के दौरान, इन दोनों फ्रिगेटों को आज, 26 अगस्त, 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

सेल ने भारतीय नौसेना के इन दोनों उन्नत युद्धपोतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के साथ साझेदारी करते हुए, अपने बोकारो, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट्स से क्रिटिकल ग्रेड की हॉट-रोल्ड शीट और प्लेट्स की आपूर्ति की। भारतीय नौसेना के लिए क्रिटिकल -ग्रेड स्टील के विकास और आपूर्ति के जरिये, सेल ने आयात प्रतिस्थापन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सीधे तौर पर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहलों से जुड़ा हुआ है और रक्षा जरूरतों के लिए विशेष गुणवत्ता वाले स्टील उपलब्ध करने की दिशा में भारत की आयात पर निर्भरता को घटाता है। अकेले राउरकेला स्टील प्लांट के 'स्पेशल प्लेट प्लांटह्व ने टैंक, युद्धपोतों और मिसाइलों जैसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एक लाख टन से भी अधिक क्रिटिकल - ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है।

आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि जैसे जहाजों को नौसेना में शामिल करना, यह दिखाता है कि भारत अब देश में ही अपने जहाजों के लिए बुनियादी स्टील से लेकर इनके जटिल डिजाइन बनाने और कुशल चालक दल तक को विकसित करने में सक्षम है, जो हमारे देश की रक्षा प्रणाली की ताकत और मजबूत नींव को प्रदर्शित करता है। भारत के रक्षा क्षेत्र के साथ सेल की स्थायी साझेदारी अच्छी तरह से स्थापित है, जिसमें आईएनएस विक्रांत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस अजय, आईएनएस निस्तार, आईएनएस अणार्ला, आईएनएस विंध्यगिरि और आईएनएस सूरत जैसे प्रतिष्ठित जहाजों के लिए महत्वपूर्ण-ग्रेड स्टील की आपूर्ति का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। यह अटूट प्रतिबद्धता एक विश्वसनीय राष्ट्रीय निमार्ता और देश के चल रहे नौसैनिक आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में सेल की स्थिति को मजबूत करता है।

'अब समझ आया क्यों कहते थे 40-50 साल रहेगी भाजपा सरकार', राहुल गांधी ने अब अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप

(जीएनएस)।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार, 26 अगस्त को बिहार के मधुबनी जिले में वोट अधिकार यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी के जरिए लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया और कहा कि अमित शाह का बयान, जिसमें उन्होंने पार्टी के 40-50 साल तक शासन की बात कही, उस 'सच' को उजागर करता है।

राहुल गांधी ने कहा कि, 'अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि भाजपा सरकार 40-50 साल तक चलेगी। इसलिए, मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उन्हें कैसे पता कि वे 40-50 साल तक सत्ता में रहेंगे? यह एक अजीब बयान था।'

अमित शाह ने कब-कहां कही थी ये बात?

अमित शाह ने 2017 में मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में यह दावा करते हुए कहा था कि, 'हम 5-10 साल के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 50 साल के लिए सत्ता में आए हैं। हमें इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि 40-50 सालों में हमें सत्ता के माध्यम से देश में बड़े बदलाव लाने हैं।'

आज देश के सामने सच्चाई आ गई- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने मंगलवार को इस टिप्पणी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि, 'आज देश के सामने सच्चाई आ गई है कि वे 'वोट चोरी' करते हैं। इसकी शुरूआत गुजरात से हुई, फिर 2014 में यह राष्ट्रीय स्तर पर आया और फिर दूसरे राज्यों में भी।'

राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ सबूतों का दिया हवाला

यह कहते हुए कि वह केवल सबूतों के आधार पर ही बयान देते हैं कांग्रेस नेता ने कहा कि, 'मैं झूठ नहीं बोलता, मैं केवल तभी कुछ कहता हूं जब मेरे पास तथ्य होते हैं।'

'बिहार के युवाओं ने किया ताकत का प्रदर्शन'

मतदाता अधिकार यात्रा के तहत बिहार के मधुबनी में एक सभा को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवाओं ने 'अपनी ताकत का प्रदर्शन' किया है, और दावा किया कि यह विरोध प्रदर्शन भाजपा नेतृत्व और चुनाव आयोग को 'वोट चुराने से पहले दो बार सोचने' पर मजबूर करेगा।

धीरे-धीरे नागरिकों के अधिकारों को खत्म करने का आरोप

उन्होंने आगे सरकार पर नागरिकों के अधिकारों को चरणों में खत्म करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि, 'पहले वोट, फिर राशन कार्ड, उसके बाद जमीन'- और कसम खाई कि विपक्ष इसे जारी नहीं रहने देगा।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री के चुनावी तंज पर पलटवार करते हुए इसी आरोप को दोहराया। उन्होंने कहा कि, 'नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था- कांग्रेस आपकी भैंस चुरा लेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद आपका वोट चुरा रहे हैं।'

अ'२ङ्ग र्फी

श्रींङ्क: 'लालू को बचाने के लिए मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ा था राहुल गांधी ने', अमित शाह ने कर

धामी सरकार ने शुरू किया नया जनजागरूकता अभियान, देहरादून की दुकानों में भी लगे स्वदेशी अपनाओ के स्टीकर

(जीएनएस)।
उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने स्वदेशी अपनाने को लेकर जनजागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। देहरादून के पलटन बाजार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ' जनजागरूकता अभियान का नेतृत्व किया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पलटन बाजार की दुकानों का भ्रमण किया तथा "स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को मजबूत बनाये" के स्टीकर लगाए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि त्योहारों, उपहारों एवं दैनिक उपयोग में स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता दें।

इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया।